

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1885  
उत्तर देने की तारीख 13/03/2023

शिक्षा हेतु बजट आवंटन

+ 1885 श्री बी. मणिकम टैगोर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत सात वर्षों के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में कमी आई है:

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2021-22 में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 1.5 प्रतिशत बनी हुई है;

(ग) क्या वर्ष 2013-14 और 2021-22 के बीच माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में विद्यालयों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): पिछले सात वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन नीचे दिया गया है-

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट
2015-16	69074.76
2016-17	72394.00
2017-18	79685.95
2018-19	85010.29
2019-20	94853.64
2020-21	99311.52
2021-22	93224.31
2022-23	104277.72
2023-24	112899.47

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, यह देखा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ख) से (घ)

#### जेंडर के आधार पर प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर

जी हां, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) 2021-22 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 1.5% है।

ड्रॉपआउट दर - प्राथमिक (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक)	
बालक	1.6
बालिका	1.4
कुल	1.5

#### माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़) 2013-14 और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) 2021-22 के अनुसार, 2013-14 से 2021-22 तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या क्रमशः 1,41,941 से बढ़कर 1,50,452 और 86,261 से बढ़कर 1,42,398 हो गई है।

स्कूल श्रेणी	2013-14	2021-22
माध्यमिक	1,41,941	1,50,452
उच्चतर माध्यमिक	86,261	1,42,398

\*\*\*\*\*